छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 11 (अक्टूबर - दिसम्बर 2019)

ईमेलः- **chhattisgarh.sccc@gmail.com** वेबसाइटः- **www.cgclimatechange.com**

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की त्रैमासिक समाचार पत्रिका के 11वें अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हमनें अण्डर टू कोयलेशन आम महासभा 2020 के साथ COP25 की जानकारी भी सम्मिलित की है, जो 02 दिसम्बर 2019 से 13 दिसंबर 2019 के बीच मैड्रिड, स्पेन में सम्पन्न हुआ।

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा 14 तथा 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अंक में भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 (एफ. एस. आई) द्वारा प्रकाशित ''इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019" की जानकारी भी सम्मिलित की गई है जो यह दर्शाता है कि भारत का ग्रीन कवर पिछले दो वर्षों में 5,188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।

इस न्यूज लेटर के आगामी अंकों में सुधार हेतु हम अपने सभी सम्मानित पाठकों के सुझावों का स्वागत करते हैं।

(मुदित कुमार सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
तथा राज्य नोडल अधिकारी, जलवायु परिवर्तन
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषय–वस्तु

- राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा 14 तथा 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया
- अंडर टू कोयलेशन द्वारा मैड्रिड, स्पेन में आयोजित आम महासभा का आयोजन
- क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ग्रेटा थुनबर्ग को 'पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चयनित किया गया
- क्या आप जानते हैं ?
- जलवायु परिवर्तन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए फुटबॉल स्टेडियम को वन में तब्दील कर दिया
- गूगल का नया उत्सर्जन टूल जो शहर के प्रदूषण के स्तर को मापने में मदद करेगा
- जलवायु परिवर्तन विषय पर बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) देशों की 29 वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 25, 26 अक्टूबर 2019 को बीजिंग, चीन में आयोजित हुई
- इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 : दो वर्षों में भारत के ग्रीन कवर में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई
- समाचार शीर्षक

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा 14 तथा 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर में दिनांक 14/10/2019 से 15/10/2019 को भारतीय वन सेवा के उच्च अधिकारियों हेतु ''सतत मानव विकास में वानिकी का योगदान'' विषय पर दो दिवसीय अखिल भारतीय अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में देश के विभिन्न राज्यों यथा तमिलनाडू, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, गुजरात, केरल, मणिपुर, मेघालय, मध्यप्रदेश, असम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य के कुल 22 भारतीय वन सेवा के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में वानिकी संबंधी महत्वपर्ण तकनीकी सत्रों के साथ–साथ प्रदेश में वानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों तथा छत्तीसगढ़ शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजना ''छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी – नरवा, गरूवा, घुरवा बाडी – ऐला बचाना है संगवारी'' का अध्ययन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री मुदित कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) सह निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस, तकनीकी सत्र में डॉ के. सुब्रमणियम, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग एवं सदस्य राज्य योजना आयोग, छ.ग द्वारा ''छत्तीसगढ में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन – अवसर एवं चुनौतियां'' विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। तदुपरांत श्री बी. आनंद बाबू, कार्यकारी निदेशक, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा ''सतत मानव विकास हेतु स्वा सहायता समूहो के माध्यम से लघुवनोपज उत्पादों का मूल्य वर्धन'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया। तकनीकी सत्र के उपरांत प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित संजीवनी मार्ट एवं प्रसंस्करण यूनिट का भ्रमण कराया गया तथा नया रायपुर में स्थित जंगल सफारी एवं म्यूजिकल फाउंटेन का भ्रमण कराया गया एवं राज्य में वानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार एवं विकास कार्यों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दूसरे दिन तकनीकी सत्र में प्रोफेसर एस. बी राय, भारतीय जैव– सामाजिक शोध एवं विकास संस्थान, कलकत्ता द्वारा ''सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकीकृत वन मोजेक लैण्डस्कैप प्रबंधन'' विषय पर; श्री प्रदीप शर्मा, सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी – नरवा, गरूवा, घुरवा बाडी– ऐला बचाना है संगवारी – छत्तीसगढ़ में सतत विकास हेतु एक अभिनव परियोजना'' विषय पर; श्री मुदित कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सह निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा ''सतत मानव विकास में वानिकी का योगदान – राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना एवं प्रमाणीकरण'' तथा श्री पी. सी मिश्रा, सेवा निवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग द्वारा ''स्थानीय स्वयंसेवी संस्थानों की वानिकी आधारीत सतत मानव विकास में भूमिका'' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिए गये ।

अंडर टू कोयलेशन द्वारा मैड्रिड, स्पेन में आयोजित आम महासभा का आयोजन

श्री मुदित कुमार सिंह, नोडल ऑफिसर, छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज द्वारा अंडर टू कोयलेशन द्वारा मैड्रिड, स्पेन में आयोजित आम महासभा में भाग लिया गया। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (COP 25) के 25वें सत्र के दौरान उक्त महासभा का आयोजन किया गया। (COP 25) सम्मेलन की 13 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद थी परन्तु कुछ मुद्दों, विशेष रूप से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु वित्त से जुड़े नुकसान के लिए वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर आम सहमति पर पहुंचने के लिए इसे 15 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया।

चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन शीर्षक से COP 25 का फैसला, निरंतर जारी उन चुनौतियों पर जोर देता है, जिनका सामना विकासशील देशों को वित्तीय, प्रौद्योगिकी और क्षमता–निर्माण सहायता तक पहुंचने में करना पड़ता है और इसने विकासशील देश पार्टियों को सहायता का प्रावधान को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है ताकि संयोजन और कमी के प्रयासों को मजबूत किया जा सके। निर्णय के दौरान विकासशील देश पार्टियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने के लक्ष्य के लिए विकसित देश पार्टियों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को भी याद करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा के मुद्दे पर, अपनाया गया निर्णय महत्वाकांक्षा का संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें न केवल जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रयास सम्मिलित हैं, बल्कि विकसित देश पार्टियों से विकासशील देश दलों को अनुकूलन समर्थन के कार्यान्वयन के साधन भी सम्मिलित हैं।

भारत शमन और अनुकूलन के बीच समानता पर जोर दे रहा है। सीओपी 25 निर्णय इस बात का स्मरण कराता है कि वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के प्रावधान का उद्देश्य अनुकूलन और शमन के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए। इसके लिए देश के स्वामित्व वाली रणनीतियों और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।

क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ग्रेटा थुनबर्ग को 'पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चयनित किया गया

टाइम पत्रिका द्वारा क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ग्रेटा थुनबर्ग को 'पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चयनित किया गया है। ग्रेटा ने यह सम्मान सबसे कम उम्र में हासिल किया है।

ग्रेटा थुनबर्ग ने स्कूल छोड़ कर एक वैश्विक आंदोलन की शुरूआत की : अगस्त 2018 से ग्रेटा थुनबर्ग ने स्कूल छोडना शुरू किया और इसकी बजाय स्वीडिश संसद के बाहर बैठकर तथा हाथों में ''स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाईमेट'' होल्डिंग लिये धरना देना शुरू किया।

पिछले 16 महीनों में ग्रेटा थुनबर्ग ने यूनाईटेड नेशन में राष्ट्रीय अध्यक्षों को संबोधित किया है, पोप के साथ मुलाकात की है, 4 मिलियन लोगों को वैश्विक जलवायु आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया साथ ही ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया जा चुका है।

ग्रेटा थुनबर्ग ने COP25 शिखर सम्मेलन, मैड्रिड, स्पेन में चिली, रूस, फिलीपींस, युगांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के युवाओं के साथ मंच साझा किया, ग्रेटा थुनबर्ग की कुछ शुरुआती टिप्पणियां निम्न हैं:

''हम यह मानते हैं कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसका उपयोग उन लोगों को आवाज देने के लिए करें, जिन्हें अपनी कहानियाँ सुनाने की जरूरत है। जलवायु आपातकाल कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह एक ऐसी चीज है, जो पहले से ही हमें प्रभावित कर रही है, लोग आज इससे पीड़ित हैं और मर रहे हैं।''

क्या आप जानते हैं ?

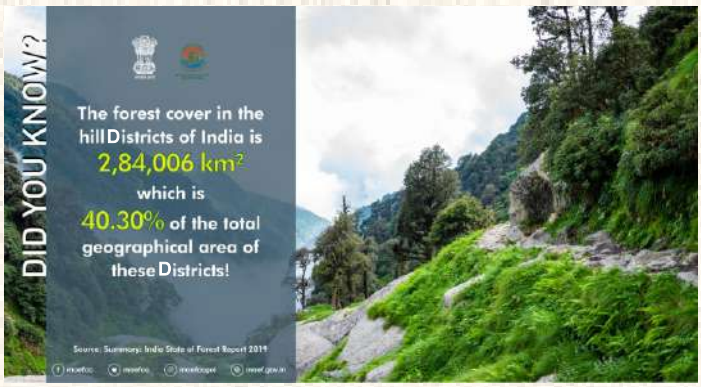

जलवायु परिवर्तन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए फुटबॉल स्टेडियम को वन में तब्दील कर दिया

प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ, जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई एक वैश्विक संकट है, और वनों की कटाई की दर में वृद्धि के साथ, विषाक्त ग्रीनहाउस गैसों से निपटने के लिए वनों द्वारा उत्सर्जित होने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए सबसे स्पष्ट समाधान अधिक पेड़ लगाना है।

स्विस क्यूरेटर क्लॉस लिटमैन बस यही कर रहे हैं। उनकी परियोजना, फॉरेस्टः द अनेंडिंग अटेंशन ऑफ नेचर, ने ऑस्ट्रिया के क्लैगनफर्ट में वॉथरसी स्टेडियम को एक अस्थायी यूरोपीय जंगल में बदल दिया है।

स्टेडियम मे लगभग 300 पेड़ हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से विकसित हैं और जिनमें से कुछ अकेले लगभग 13,227 पाउंड वजन के हैं, जल्द ही यह स्टेडियम के मौजूदा एस्ट्रोटर्फ पर पूर्ण रूप से छा जायेंगे और साथ ही यह देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक कला की जगह होगी।

इनिया लैंडस्केप आर्किटेक्चर के सहयोग से विकसित इस क्यूरेटेड जंगल में सिल्वर बर्च, एल्डर, एस्पेन, व्हाइट विलो, फील्ड मैपल और ओक सहित कई प्रजातियां हैं। टीम ने इटली, जर्मनी और बेल्जियम इन देशों की नर्सरी से इन पेड़ों को लाया और सार्वजनिक कला की स्थापना के लिए टीम कोऑस्ट्रिया में पेड़ों के पहुंचाने में 22 दिन लगे।

Source:-https://www.fastcompany.com/

गूगल का नया उत्सर्जन टूल जो शहर के प्रदूषण के स्तर को मापने में मदद करेगा

गूगल ने क्लाइमेट चेंज की मदद के लिए एक नए टूल की घोषणा की है। इसका नया प्रोडक्ट, इनवायरोनमेंटल इनसाइइट एक्सप्लोरर, भवन उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग करता है। इस डेटा के साथ, शहर नीतियां बनाई जा सकती हैं तथा बेहतर अनुमान लगाया जा सकता हैं।

यह टूल सर्वप्रथम यूरोप में पहले लॉन्च होगा तथा डवलिन के साथ शुरूवात होगी। कोपेनहेगन में, Google सड़क स्तर की वायु गुणवत्ता की जानकारी दिखाएगा। यह वायु गुणवत्ता डेटा प्रत्येक ब्लॉक पर ब्लैक कार्बन और पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को दर्शाता है। यह नंबर परिवहन से प्रभावित हैं और इसका उपयोग यातायात मार्गों की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। शहर के जनप्रतिनिधि इस परिवर्तन और संभावित परिवर्तन को देख सकते हैं।

यह प्रोडक्ट ग्लोबल कॉन्वेंट फॉर मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी (GCoM) के सहयोग से बनाया गया है। GCoM एक संगठन है, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शहर कितने अच्छे हैं। इनमें से कई महापौर C40 शिखर सम्मेलन में वर्तमान रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं।

डबलिन सिटी के चीफ एक्जिक्यूटिव ओवेन कीगन ने कहा, ''अब हम पर्यावरण उत्सर्जन से संबंधित बातचीत के लिए इनवायरोनमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर, को उपयोग में ला सकते है, साथ ही लोगों को ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करने का प्रभाव दिखा सकते हैं जो उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

जलवायु परिवर्तन विषय पर बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) देशों की 29 वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 25, 26 अक्टूबर 2019 को बीजिंग, चीन में आयोजित हुई।

जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक बीजिंग, चीन में 25–26 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई। चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री श्री ली गानझाई ने बैठक की अध्यक्षता की और चीन के जलवायु परिवर्तन मामलों के विशेष प्रतिनिधि श्री शाय झेनहुआ और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्री मा. श्री प्रकाश जावड़ेकर; ब्राजील के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राष्ट्रीय सचिव श्री रॉबर्टो कैस्टेलो ब्रैंको और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंध और वार्ता के मुख्य निदेशक श्री माइसेला केकाना ने इसमें भाग लिया।

बेसिक मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों की वैश्विक चुनौती के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को हल करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने, कम–कार्बन और सतत विकास के साथ बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। उन्होंने सभी की भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तैयारियों के लिए सामूहिक रूप से काम करने पर जोर दिया। मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दलों को अलग–अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का बचाव करना चाहिए, जो कि समानता आधारित, किन्तु अलग–अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर–आरसी) के सिद्धांतों के अनुसार है। बहुपक्षीय प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर ध्यान देना आवश्यक है।

मंत्रियों ने बताया कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है, लेकिन शमन की तुलना में संसाधनों के असंतुलित आवंटन के कारण यह उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) सहित विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के संदर्भ में अनुकूलन और शमन के लिए संतुलित आवंटन किया जाना चाहिए। समूह ने अनुकूलन पर विकासशील देशों के समर्थन में अपनी भूमिका निभाने के लिए वैश्विक आयोग सहित अन्य मंचों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों में वित्तीय अनुकूलन के लिए अनुच्छेद 6 के तहत आईटीएमओ लेनदेन से प्राप्त आय का एक हिस्सा इस कार्य में लगाना महत्वपूर्ण है।

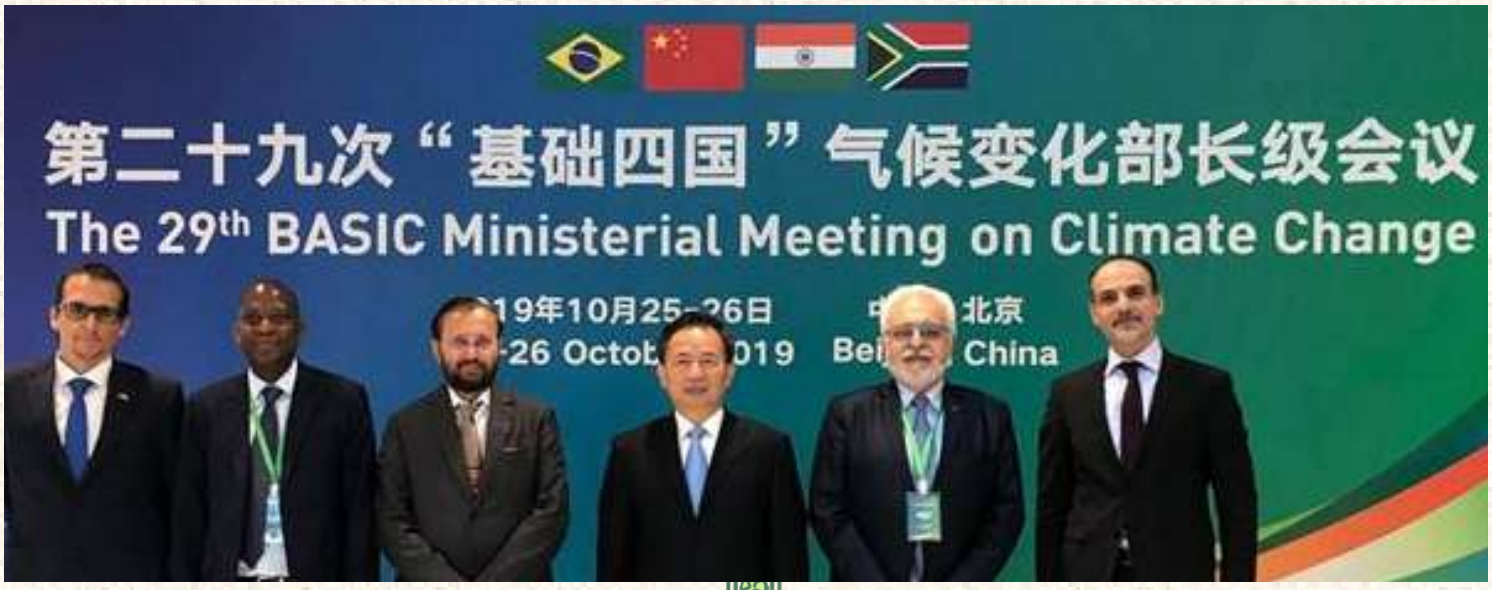

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 : दो वर्षों में भारत के ग्रीन कवर में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई

श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश के वन क्षेत्र की स्थिति (आईएसएफआर) पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की गई है। इस पर देश के वन और वृक्ष संपदा के आकलन के साथ ही हर दो वर्ष पर वन क्षेत्र का नक्शा बनाए जाने की जिम्मेदारी है। आईएसएफआर 1987 से यह काम कर रहा है। उसकी ओर से अबतक देश के वन क्षेत्र का 16 बार आकलन किया जा चुका है और इस संबंध में वह ताजा रिपोर्ट के साथ अबतक 16 रिपोर्ट जारी कर चुका है।

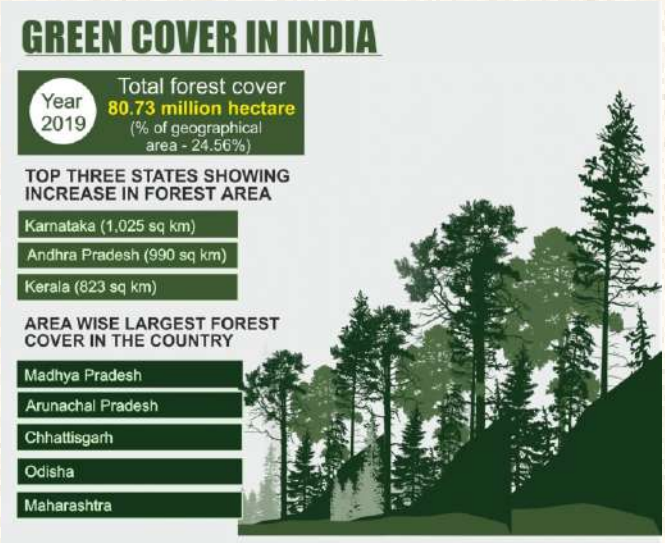

रिपोर्ट जारी करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में से है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ताजा आकलन के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 2017 के आकलन की तुलना में देश में इस बार वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का कुल दायरा 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है "इसमें वन आच्छादित क्षेत्र का दायरा 3976 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का दायरा 1212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वन क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी खुले और सामान्य रूप से घने तथा बेहद घने जंगलों में देखी गई है। सघन वन क्षेत्रों में विस्तार के मामले में कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, और केरल शीर्ष तीन राज्यों में से रहे। कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्रप्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर का और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है।.

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

वन आच्छादित क्षेत्र के विषय में मध्यप्रदेश पहले नंबर पर रहा। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर जबकि छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद ओडिशा और महाराष्ट्र का नबंर रहा। देश के कुल भौगालिक क्षेत्र के अनुपात में वनआच्छादित क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी के मामले में मिजोरम (85.41%) प्रतिशत); अरुणाचल प्रदेश (79.63%); मेघालय (76.33%); मणिपुर (75.46%) और नागालैंड (75.31%) पांच शीर्ष राज्य रहे।

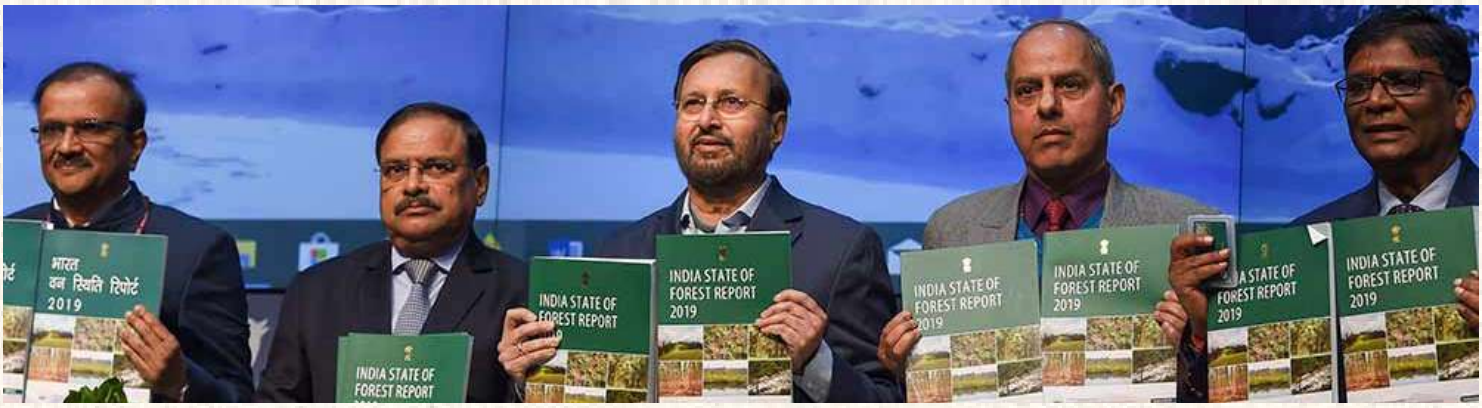

समाचार शीर्षक

पर्यावरण: 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में 'नेट जीरो' की स्थिति पाना चाहता है भारतीय रेलवे

उत्सर्जन घटाने की ओर बढ़ रहा रेलवे!

अमेरिका और चीन के बाद भारत वातावरण जैसे का सामने यहा उत्सर्जक है और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक माना जाता है। जलवायु परिवर्तन को महाकाल करने की बजट की रणनीति के तहत, भारतीय रेलवे 2030 तक 'शून्य शून्य' कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, यह दावा हाल में रेलवे व महिन्द्रा और पेट्रोल लोयल ने किया।

रेलवे के विद्युतीकरण सहित अन्य प्रयासों का भी इसमें बड़ा हाथ होगा। रेलवे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और वातावरण के तहत भूमि भी है, इस भूमि का सौर-ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

रेलवे बनेगा 'जलवायु जस्टिस' कार्रवाई का अभिन्न हिस्सा!

नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर

पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयोग

पत्रिका Thu, 17 October 2019

शहर के एक प्लास्टिक उद्यमी का प्रयोग

प्लास्टिक जैसा कैरीबैग जो नष्ट होकर खाद बनेगा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

रायपुर. नो-प्लास्टिक अभियान के अंतर्गत अब शहर के एक प्लास्टिक उद्योग में नई तकनीक और नए अनुप्रयोग से इसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। इसके अंतर्गत अब शहर में ऐसे कैरी बैग की तकनीक ईजाद की जा चुकी है, जिसे प्लास्टिक का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि 6 महीने के भीतर यह मिट्टी में मिलकर खाद का रूप ले सकती है। इसे इको फ्रेंडली कम्पोस्टेबल बैग्स का नाम दिया गया है।

सेजबाहर स्थित बृजकांकी प्लास्टिक उद्योग में यह निर्माण शुरू हो चुका है। कंपनी के जीएम विकास अग्रवाल ने बताया कि उनका यह विशेष कैरी बैग केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है, जिसे एनओसी मिल चुकी है। वहीं राजधानी स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी (सीपेट) ने भी इको फ्रेंडली कम्पोस्टेबल बैग्स की कीमत प्लास्टिक से तीन गुणा महंगी है। बाजार में इसकी न्यूनतम कीमत 400 रुपए किलो है। छग प्लास्टिक निर्माता संघ के अध्यक्ष संतोष जैन व प्लास्टिक कारोबारी अमित धावना ने बताया कि प्लास्टिक को लेकर दिशा-निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि नियमों के मुताबिक उत्पाद बनाए जा सकें।

पत्रिका अभियान प्लास्टिक को ना

सर्टिफाइड किया है। कम्पोस्टेबल बैग का उपयोग करने के बाद इसका वेस्ट मिट्टी के साथ मिलने पर 90 से 180 दिनों के भीतर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।

प्लास्टिक से महंगा फिर भी आएगा चलन में

1 लाख विद्यार्थियों ने ली नो प्लास्टिक की शपथ

मिंगल पूजड़ प्लास्टिक के विरुद्ध चल रहे महा अभियान में मंगलवार को नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी व ग्रीन आर्मी के साथ मिलकर 221 स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थियों ने नो टू प्लास्टिक कहा और लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने नो टू प्लास्टिक की शपथ ली। इस संकल्प दिवस पर हर स्कूल व कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर प्रमोद दुबे महाराणा अवसेन कॉलेज के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए सभी को संकल्प दिलाया। ग्रीन आर्मी से जुड़े 15 सौ सदस्यों को इस शपथ कार्यक्रम के लिए स्कूलों व कॉलेजों में तैनात किया गया था। इसके लिए 11 मिनट के सक्षिप्त कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, विकल्प बताने के साथ रायपुर को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमेन राजेश अग्रवाल, ग्रीन आर्मी के फाउंडर अमिताभ दुबे, रायपुर स्मार्ट सिटी व नगर निगम के अधिकारी शामिल थे।

डिस्पोजल पर रोक लगाने 'बर्तन बैंक'

राजधानी में डिस्पोजल के उपयोग पर रोक लगाने के लिए 'बर्तन बैंक' योजना की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत सामजिक कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले डिस्पोजल पर रोक लगाने के लिए मुफ्त में बर्तन देने की पहल की जा रही है। संगठन के संयोजक राज बजाज ने बताया कि शादी-विवाह, जन्म दिन व दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में डिस्पोजल का उपयोग किया जाता है। इसे रोकने के लिए लोगों को बर्तन बैंक से प्लेट, गिलास व कटोरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए लोगों को अपनी एक आईडी और नॉमिनल राशि डिपाजिट के रूप में जमा करनी होगी। बर्तन का उपयोग करने के बाद वापस करने पौरान डिपाजिट राशि वापस की जाएगी। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू किया जा रहा है। अभी संस्था ने 50 हजार प्लेट और गिलास उपलब्ध करने की तैयारी की है।

मिशन 2025 : जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने की दिशा में यूरोपीय देश डेनमार्क की तैयारी

कार्बन प्रदूषण मुक्त पहला शहर बनेगा कोपेनहेगन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोपेनहेगन. जलवायु परिवर्तन पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन 2025 तक विश्व का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त शहर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हर कोई अपने दैनिक कार्य के लिए पैदल, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही चुनते हैं। कम ही लोग सड़कों पर कार लिए दिखेंगे। इतना ही नहीं यह शहर तेल और गैस के उपयोग में कमी लाने के लिए भी काम कर रहा है। 2005 से अब तक शहर का कार्बन उत्सर्जन 42 प्रतिशत कम हो चुका है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोपेनहेगन तेजी से आगे बढ़ रहा है।

14 साल में 42% कम हुआ शहर का कार्बन उत्सर्जन

कोपेनहेगन की सड़कों पर लोग साइकिल से चलते हैं।

ये हैं तैयारियां

- शहर में 100 नई विंड टर्बाइन लगाकर बिजली की खपत में 20 प्रतिशत की कमी लाना।
- 60 हजार वर्ग मीटर के नए सोलर पैनल और घरों को गरम करने में 100 प्रतिशत ऊर्जा जरूरत अक्षय ऊर्जा के जरिए प्राप्त करने का लक्ष्य।
- 75% यातायात, पैदल और साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही पूरा करना। अभी यह आंकड़ा 35% के करीब है।
- शहर से निकलने वाले आर्गेनिक कचरे का बायोगैस बनाने में प्रयोग इस्तेमाल, इससे सफाई और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेगा।

सही वातावरण से जीता विश्वास

जलवायु अनुकूलन कंपनी ग्रीनोवेशन के सीईओ, कजिल्डगार्ड कहते हैं," हमने जीवन गुणवत्ता को स्थिरता के साथ जोड़ दिया और इसे ही 'जीवंतता' कहा। हम इसके चारों ओर एक अच्छा वातावरण बनाने में सफल रहे, जिस पर हर कोई विश्वास कर सकता था। विश्व के सबसे अच्छे शहरों में शुमार कोपेनहेगन शहर जीलैंड और अमागर नामक द्वीपों पर बसा हुआ है। दुनियाभर के पर्यटकों के लिए यह शहर तो स्वर्ग से कम नहीं है।

सम्पादक मंडल

- श्री मुदित कुमार सिंह (मुख्य संपादक)
- श्री बी. विवेकानंदा रेड्डी
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- डॉ राजेश गुप्ता
- श्री जे. ए. सी. एस राव
- श्री मानस उज्जैनी
- श्री अभिनव अग्रहरि

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर
विधान सभा के पास, बलौदा बाजार रोड, जीरो प्वाइंट
रायपुर – 493111, छत्तीसगढ़
फोन : 0771 – 2285120
ईमेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgclimatechange.com